जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 82 प्रभात हिण्डौन सिटी, शुक्रवार 24 जनवरी, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

20 फरवरी को ''डैडलाइन'' से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये दौड़ लगी

इस दौड़ में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय गर्भवती महिलाओं की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के जन्म आधारित नागरिक अधिकार खत्म करने के कार्यकारी आदेश के बाद, अमेरिका के दम्पतियों, जो माता-पिता बनने वाले हैं, में 20 फरवरी से पहले सी सैक्शन से बच्चे को जन्म देने की होड़ लग गई है। ट्रम्प ने 20 फरवरी की डैडलाइन दी है जन्म आधारित नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने के लिए।

इन मामलों में से अधिकांश भारत के हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह चलन दक्षिण एशियाई देशों के अलावा अन्य देशों में भी है, क्योंकि हरेक व्यक्ति मामूली सी संभावना होने पर इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है।

ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा बच्चे को होगा, क्योंकि जो महिलाएं सी सैक्शन का विकल्प चुन रही हैं, वे गर्भावस्था में आठवें या नवें महीने में है। गर्भावस्था की अवधि पूरी होने में कुछ ही समय बचता है, पर इससे बच्चे को खतरा हो सकता है।

- ये महिलाएं, जिन्हें गर्भ धारण किये आठ या नौ महीने ही हुए हैं, ''डैडलाइन'' से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये, अमेरिका में डॉक्टरों पर ''सिज़ेरियन'' प्रक्रिया से बच्चे को जन्म देने के लिए दबाव डाल रही हैं। हालांकि, डॉक्टर उन्हें बार-बार सलाह दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया से बच्चे की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- समय से पूर्व जन्मे ऐसे बच्चों में फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इन बच्चों को माँ का स्तनपान करने में भी कठिनाई होती है। इन बच्चों का जन्म के समय वजन भी बहुत कम होता है तथा कुछ बच्चों में ''न्यूरोलॉजिकल प्रॉबलम्स'' भी विकसित हो जाती हैं।
- ट्रम्प द्वारा निर्धारित डैडलाइन का उन लाखों भारतीयों पर असर पड़ेगा, जो अमेरिका में अस्थायी वीज़ा प्राप्त करके रह रहे हैं।
- क्योंकि, अमेरिका में ''ग्रीन कार्ड'' प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, उन भारतीय दम्पतियों के लिए यह एक ''सेफ्टी नैट'' है, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और उनकी पत्नियां गर्भवती हैं।

न्यूजर्सी की मैटरनिटी क्लीनिक में कार्यरत डॉ. एस.डी. रामाराव ने कहा कि उनसे समय से पूर्व डिलीवरी कराने के लिए कई लोगों ने आग्रह किया है। एक महिला का मार्च में बच्चा होना है, वह सात माह की गर्भवती है, पर अपने पति के साथ समय से पहले डिलीवरी के लिए आई थी।

अस्थाई रुप से अमेरिका में रह रहे लोगों में जन्म आधारित नागरिकता के अधिकार की डैडलाइन 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ लगी है, ताकि बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए।

जन्म के आधार पर स्वत: नागरिकता मिल जाने के अधिकार को खत्म करना इमिग्रेशन नीति में बड़ा बदलाव है तथा इससे अमेरिका में अस्थायी वीसा पर रह रहे लाखों भारतीय प्रभावित होंगे।

जन्म आधारित नागरिकता एक कानूनी सिद्धांत है, जो अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को अमेरिका का नागरिक बनने का अधिकार देता है, भले ही उसके माता-पिता किसी भी देश के हों और उनकी इमिग्रेशन स्थिति चाहे जो हो।

डॉ. एस.जी. मुक्काला ने लोगों को समय पूर्व प्रसव के सम्बंध में चेतावनी दी और कहा कि ऐसे बच्चों के फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं, उन्हें फीडिंग में समस्या होती है, उनका वजन कम होता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीमकाथाना व गंगापुर सिटी जिला समाप्ति मामले की सुनवाई 28 जनवरी को

जयपुर, 23 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नव सृजित नीमकाथाना जिले का दर्जा समाप्त करने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले को समान प्रकरण में गंगापुर सिटी के मामले में रामकेश मीणा की ओर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने को कहा है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक रमेश चंद्र खंडेलवाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। वहीं, मामले में नीमकाथाना बार

- हाई कोर्ट में सरकार की ओर से इस मामले में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने पैरवी की।

एसोसिएशन की ओर से भी याचिका पेश की गई है।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पेश हुए। उनकी ओर से याचिका में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर खंडपीठ ने याचिका को रामकेश मीणा की याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है। याचिका में अधिवक्ता निखिल सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों और तय मापदंडों के आधार पर नीम का थाना सहित, अन्य जिलों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हम हमेशा, ''बिना कागज़ात'' अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को वापस भारत भेजने के पक्ष में रहे हैं'

विदेश मंत्री जयशंकर को ट्रम्प प्रशासन के लगातार दबाव के कारण प्रैस कॉन्फ्रैंस में सार्वजनिक रूप से कहना ही पड़ा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। अवैध प्रवासियों, जिनमें कई भारतीय भी हैं, के खिलाफ ट्रम्प सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि उनका देश अनाधिकृत भारतीयों की वापसी के लिए खुला है।

हालांकि यह सच है कि भारत ने अवैध रुप से विदेश, खासकर अमेरिका, जाने वाले भारतीयों के खिलाफ कभी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। भारतीयों में अमेरिका के प्रति बेहद रुझान है, जिसे अधिकांश लोग सोने की खान मानते हैं।

जयशंकर के पास यह कहने के सिवा कोई चारा नहीं था कि भारत में उन लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें अमेरिका से निर्वासित किया जा सकता है, अभी इनकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है।

भारतीयों का रुस की सेना में शामिल होना, हमास के खिलाफ इज़रायल की सेना के साथ लड़ना, इस बात का सबूत है कि भारत में बेरोजागारी कितनी ज्यादा है। लेकिन सरकार इस

- पर, यह भी सच है कि अभी तक, आज तक, भारत सरकार ने भारत से अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से जाने वाले भारतीयों को रोकने का कोई गंभीर प्रयास भी नहीं किया।
- भारत में भारी बेरोज़गारी के कारण देश के मध्यम वर्ग या लोअर मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे, दलालों को पैसा देकर, विदेश (अमेरिका) जाने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं।
- बेरोज़गारी के ही कारण भारतीय युवक रूस की सेना में और हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए इज़रायल सेना में भर्ती हुए।
- पर, जब अमेरिका का वीज़ा प्राप्त करने में 400 दिन लगते हैं तो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाकर नौकरी करने के इच्छुक नौजवानों को कैसे रोका जा सकता है।
- विदेश मंत्री ने इस तर्क के प्रति अमेरिका के विदेश मंत्री (सैक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रुबिओ ने भी सहमति जताई।

प्रवृति को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जहां अमीर लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, इनमें से कई तो छोटे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय व निम्न मध्यम वर्गीय युवा गैर कानूनी तरीकों से अलग-अलग देशों में जाने का प्रयास

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप अपने लिए भाजपा से बड़ा खतरा कांग्रेस को मानती है

आप को डर है कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक वोट बैंक को खंडित ना कर दे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। आम आदमी पार्टी सार्वजनिक रूप से यह दावा भले ही कर रही हो कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि दिल्ली में करीब 10 सीटें ऐसी हैं, जहाँ आप, कांग्रेस पार्टी के प्रचार-अभियान पर खास नज़र रखे हुये है।

पिछले दो सप्ताह से, आप नेता दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस को ''अप्रासंगिक'' बता रहे हैं तथा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के साथ इसकी ''मिलीभगत'' है।

आम आदमी पार्टी, अन्य सीटों के अलावा, ओखला, चाँदनी चौक तथा बादली सीटों पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर मानकर चल रही है।

जहाँ ओखला में पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ अहमद खान की बेटी अरीबा खान आप के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मैदान में है, वहीं

- दिल्ली की दस विधानसभा सीटों पर आप कांग्रेस के प्रचार अभियान पर पैनी नज़र रखे हुए है।
- इन दस सीटों में से तीन, ओखला, चाँदनी चौक और बादली में तो आप, कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना से चिंतित है।

चाँदनी चौक सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जे.पी. अग्रवाल के पुत्र मुदित अग्रवाल, आप के पुनर्दीप सिंह साहनी के खिलाफ खड़े हैं, जो चाँदनी चौक से वर्तमान विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के पुत्र हैं। बादली सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, आप के अजेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

आप के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ''हमारे लिये, चिन्ता का विषय यह नहीं है कि कांग्रेस सीटें जीतेगी, बल्कि चिन्ता का विषय यह है कि स्वयं तो हार जायेगी, लेकिन भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने में जरूर मदद करेगी।'' उन्होंने कहा, ''भाजपा पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है तथा यह चुनाव उसके लिये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने से भाजपा की ही मदद होगी।''

आप के एक अन्दरूनी व्यक्ति ने कहा, ''देखिये, 2017 के एमसीडी चुनावों में क्या हुआ था। केवल दो साल पहले, आप ने विधानसभा चुनाव 54 प्रतिशत के विशाल वोट-शेयर के साथ जीते थे तथा कांग्रेस केवल 10 प्रतिशत वोट ही पा सकी थी। लेकिन कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव अच्छी तरह लड़े। (नतीजा यह हुआ कि) आप का वोट शेयर गिरकर 26 प्रतिशत पर आ गया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य के 5897 गाँव अभावग्रस्त घोषित

जयपुर, 23 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ बाढ़ एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 20 जिलों के 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराबे वाले 5897 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि आदान अनुदान वितरण की स्वीकृति दी।

प्रभावित किसानों को बड़ा संबल मिलेगा। इस निर्णय के उपरान्त, अब आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मानसून वर्ष 2024 (संवत् 2081) में बाढ़ और ओलावृष्टि से खरीफ फसलों के खराबे के आकलन के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए थे और जिला कलक्टरों से प्राप्त नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में व्याप्त गंदगी के लिए केजरीवाल पर कटाक्ष किया, योगी आदित्यनाथ ने

क्या केजरीवाल व उनकी सरकार के लोग यमुना में डुबकी लगाने को तैयार हैं?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में यमुना नदी में लाखों लोगों के स्नान करने का श्रेय लेते हुये, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविन्द केजरीवाल पर तंज करते हुये, उनसे तथा उनके मंत्रियों से पूछा कि क्या वे लोग दिल्ली में प्रदूषित यमुना में स्नान करने की हिम्मत कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया तथा मतदाताओं से आसन्न दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को समर्थन देने का अनुरोध किया। योगी ने जनसभा में उपस्थित भारी भीड़ से

- जैसा कि विदित है कि महाकुंभ के अवसर पर योगी व उनके मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई थी, जो बहुत प्रचारित रही थी।
- योगी ने दिल्ली और समीपवर्ती गाज़ियाबाद, जो उत्तर प्रदेश का शहर है, की तुलना की और कहा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा, आप सरकार दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई।

विकास, कानून-व्यवस्था में सुधार तथा भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन का वादा किया।

दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर की बिगड़ती हुई स्थिति का हवाला देते हुये, उन्होंने कहा, ''यह राष्ट्रीय राजधानी है। एन.डी.एस.सी. क्षेत्र के अलावा, दिल्ली की सड़कों, जल-आपूर्ति तथा बिजली की हालत देखिये। एक दशक पहले, यहाँ लोग बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैट्रो सेवा तथा सफाई के कारण आया करते थे। लेकिन अब, इस सरकार ने इसकी कैसी हालत कर दी है। सड़कों में गड्ढों की भरमार है तथा कुछ स्थानों पर तो यह बताना मुश्किल है कि क्या गड्ढों में कहीं सड़क है। हर जगह कूड़ा-करकट तथा धूल-मिट्टी दिखाई देती है।''

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप सरकार पर प्रहार करते हुये, उस पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है तथा पेयजल संकट है। आप सरकार इन मूलभूत मुद्दों के समाधान में असफल रही है।''

आप नेतृत्व की आलोचना करते हुये, आदित्यनाथ ने उस पर वास्तविक स्थिति की तुलना में सोशल मीडिया को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ''जनता के लिय काम करने के बजाय, आप नेता, जिनमें अरविन्द केजरीवाल भी शामिल हैं, अपना समय झूठे ट्वीट करने में गुजारते हैं। अगर उन्होंने ऐसे प्रयास प्रशासन के मामले किये होते, तो दिल्ली का कायापलट हो सकता था।''

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की तुलना करते हुये आदित्यनाथ ने कहा, ''दिल्ली और गाज़ियाबाद की सड़कों में सार्वजनिक सुविधाओं में जबरदस्त अन्तर है। आप ने दिल्लीवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है।''

गुजरे समय के विवादों का हवाला देते हुये, आदित्यनाथ ने कहा, ''2020 में, दिल्ली शहर दंगों का साक्षी बना तथा (दंगों में) एक आप पार्षद की लिप्तता सामने आई। आप सरकार शान्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगातार असफल रही है।''

चेक बाउन्स केस में रामगोपाल वर्मा को तीन माह की जेल

मुंबई, 23 जनवरी। महाराष्ट्र में मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को चेक अनादरण (बाउन्स) मामले में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। एक वकील ने यहां गुरुवार को बताया कि वर्मा के खिलाफ सात साल पहले परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया

- सात साल पुराने केस में अदालत ने तीन माह के भीतर 3.72 लाख का जुर्माना भरने के निर्देश दिए वरना 3 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी।

गया था।

अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने न्यायालय में पेश न होने की वजह से मंगलवार को वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया।

अदालत ने वर्मा को 3.72 लाख

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई

नई दिल्ली, 23 जनवरी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर पंजाब पुलिस के जवान जो केजरीवाल की

- आप पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती केजरीवाल की सुरक्षा कम की।

सुरक्षा में तैनात थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित हैं और इस वजह से दिल्ली पुलिस से जानकारी साझा कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। इस बीच संजय सिंह ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका की डब्ल्यु.एच.ओ. छोड़ने की घोषणा से भारत पर काफी चिन्ताजनक असर होगा

पोलियो की रोकथाम, टीबी आदि को खत्म करने के लिये गये ''इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम'' फण्ड के अभाव में सिकुड़ सकते हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में अपने पहले दिन कई कार्यकारी आदेश जारी किए, उनमें से एक थी, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (डब्ल्यु. एच.ओ.) से अमेरिका की निकासी की घोषणा। यह निकासी, जो एक वर्ष बाद प्रभावी होगी, भारत पर कई सीधे और अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है। यह इस पर निर्भर करेगा कि ग्लोबल हैल्थ इकोसिस्टम इस बदलाव के साथ कैसे एडजस्ट करता है।

अमेरिका का डब्ल्यु.एच.ओ. में प्रमुख योगदान रहा है। इसकी निकासी से एक महत्वपूर्ण वित्तीय कमी उत्पन्न हो सकती है, जो विश्वभर में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकती है। भारत, जो पोलियो उन्मूलन, तपेदिक (टीबी) उन्मूलन और टीकाकरण अभियानों जैसी डब्ल्यु.एच.ओ. द्वारा संचालित पहलों का प्रमुख प्राप्तकर्ता है, को इन कार्यक्रमों में देरी या धन की कमी का सामना कर सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि गावी (वैक्सीनेशन अलायंस) जैसी विशिष्ट पहल, जो डब्ल्यु.एच.ओ. प्रयासों से जुड़ी हुई हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो

- जैसा कि विदित ही है, कोविड-19 के दौरान डब्ल्यु.एच.ओ. की गाइडलाइन्स, रिसर्च तथा सप्लाई श्रृंखलाओं का नैटवर्क बहुत काम आया था, महामारी से जूझने में।
- भारत को यूरोपियन यूनियन, चीन व रूस की ओर देखना होगा और अधिक सहयोग व अन्य मदद के लिये, अन्यथा, भारत के रिसोर्सेज़ व कुटनीतिक ऊर्जा पर भारी दबाव रहेगा, डब्ल्यु.एच.ओ. में अमेरिका की कमी को पूरी करने के लिए विकल्प ढूंढ़ने में।

सकती हैं और भारत के टीकाकरण प्रयासों पर असर डाल सकती हैं।

दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों को डब्ल्यु.एच.ओ. से स्वास्थ्य संकटों के समाधान के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और समर्थन प्राप्त होता है। डब्ल्यु.एच.ओ. के कमज़ोर पड़ने से भारत की क्षेत्रीय हैल्थ लीडर की भूमिका प्रभावित होगी और हैल्थ एमरजैंसी के समय भारत को अपने पड़ोसी देशों की अधिक सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अमेरिका की डब्ल्यु.एच.ओ. से निकासी से ग्लोबल हैल्थ गवरनैंस में एक रिक्त स्थान पैदा होगा, जिसमें भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूत करना पड़ सकता है और यूरोपीय संघ, चीन और रूस जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ मिलकर बहुपक्षीय सहयोग को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ सकता है। इससे भारत की कूटनीतिक क्षमता और संसाधन प्रभावित हो सकते हैं।

डब्ल्यु.एच.ओ. के कमज़ोर होने से भारत को अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमताओं को बढ़ाना पड़ सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि भारत को, ग्लोबल फंड या गेट्स फाउंडेशन जैसे अन्य ग्लोबल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)